



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 7 जुलाई, 2008 / 16 आषाढ़, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 जुलाई, 2008

संख्या : पी.एल.जी-ए (3)-1/94.- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या: पी.एल.जी-ए(3)1/94 तारीख 19-4-1996 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश योजना विभाग (राज्य योजना तन्त्र) निजी सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश योजना विभाग (राज्य योजना तन्त्र) निजी सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (पांचवां संशोधन) नियम, 2008 है।

2. ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध "अ"का संशोधन.- हिमाचल प्रदेश योजना विभाग (राज्य योजना तन्त्र) निजी सहायक वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 के उपाबन्ध (अ) में :-

(क) विद्यमान स्तम्भ संख्या 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

भर्ती की पद्धतिय भर्ती सीधी होगी	पतप्रतिपत प्रोन्नति द्वारा,
या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,	ऐसा न होने पर सैकण्डमैट
स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न	आधार पर या
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों	स्थानान्तरण द्वारा ।
की प्रतिपतता:	

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
 “वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई है, को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक तथा कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संयुक्ततः ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में चार वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल सम्मिलित होगा, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से समतुल्य वेतनमान में कार्यरत् इस पद के पदधारियों में से सैकण्डमैट आधार पर या स्थानान्तरण द्वारा ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने-अपने प्रवर्ग/ पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण : अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल प्रदेश स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिजस, रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन, (रिजर्वेशन ऑफ वैकनसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भरती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी”।

आदेश द्वारा,
हस्ता/—
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of the Government Notification No PLG-A (3)-1/94 dated PLG-A (3) 1/94 dt.3rd July, 2008 as required, under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd July, 2008

No PLG-A (3)-1/94.— In exercise of the power conferred by Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Planning Department (State Planning Machinery) Personal Assistant Class-II, (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 notified vide this department Notification No PLG-A (3)-1/94 dated 19-4-1996, namely:-

1. Short title and commencement.— (i) These Rules, may be called the Himachal Pradesh Planning Department (State Planning Machinery) Personal Assistant (Class-II, Non Gazetted) Recruitment and Promotion (Fifth Amendment), Rules, 2008

(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure “A”.— In Annexure “A” to the Himachal Pradesh Planning Department (State Planning Machinery) Personal Assistant (Class – II Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rule 1996;

(a) For the existing Column No 10, the following shall be substituted, namely:-

(a)	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various method.	100% by promotion failing which secondment basis or by transfer.
-----	---	--

- (b) For the existing provision against Column No 11, the following shall be substituted, namely:-

“By promotion from amongst the Senior Scale Stenographers having six years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Senior Scale Stenographers with eleven years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any combined as Senior Scale Stenographer and Junior Scale Stenographer, which shall include four years essential service as Senior Scale Stenographer failing which on secondment basis or by transfer from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other H.P Government Departments.”

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION : The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder;

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post , if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion has been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules;

Provided that the inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

श्रम विभाग**अधिसूचनाएं**

शिमला-171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Parmar Singh S/O Shri Dayala Ram C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dinesh Singh, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Dinesh Singh, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Parmar Singh S/O Shri Dayala Ram workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Padam Singh Bohra S/O Shri Nante Singh Bohra C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Rajeev Saini, M/S Kushal Builder, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Rajeev Saini, M/S Kushal Builder, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to re-engage Shri Padam Singh Bohra S/O Shri Nante Singh Bohra workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Khairati Lal S/O Shri Jitu Ram C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Subhash Kumar, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Subhash Kumar, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Khairati Lal S/O Shri Jitu Ram workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Janak Raj S/O Shri Nidhia Ram C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Kamlesh Morya, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Kamlesh Morya, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Janak Raj S/O Shri Nidhia Ram workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ghinder Singh S/O Shri Madho Ram C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Lakhan Rawla, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Lakhan Rawla, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Ghinder Singh S/O Shri Madho Ram workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Laxman Singh S/O Shri Paras Ram C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Lakhan Rawla, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Lakhan Rawla, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Laxman Singh S/O Shri Paras Ram workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ganesh Sau S/O Shri Nirandan Sau C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chouhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Ganesh Sau S/O Shri Nirandan Sau workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Hari Sharma S/O Shri Janak Sharma C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chauhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Ashok Chauhan, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Hari Sharma S/O Shri Janak Sharma workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Mustaq Mohmmad S/O Shri Mantu Mohmmad C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Kamlesh Morya, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Kamlesh Morya, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Mustaq Mohmmad S/O Shri Mantu Mohmmad workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Madan S/O Shri Gian Chand C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Kamlesh Morya, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Kamlesh Morya, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Madan S/O Shri Gian Chand workman after 01-09-2006 when the company restarted the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Dil Bahadur S/O Shri Manvir Gharti C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/ औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को

उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Dil Bahadur S/O Shri Manvir Gharti workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.- अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Dil Bahadur S/O Shri Manvir Gharti C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/ औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Dil Bahadur S/O Shri Manvir Gharti workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Sudam Naik S/O Shri Kandua Naik C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/ औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Sudam Naik S/O Shri Kandua Naik workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ram Bahadur Tamang S/O Shri Man Bahadur Tamang C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/ औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Ram Bahadur Tamang S/O Shri Man Bahadur Tamang workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

शिमला-171001

संख्या :11-5/99(Lab)ID/ 07-Chamba.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Raj Kumar S/O Shri Kehar Singh C/O CITU Office, Prem Niwas, Upper Julakri, Chamba, District Chamba, H.P. V/S (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/ औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

“Whether the action of the (1) The Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. (2) Shri Karan Salaria, Sub Contractor C/O Project Manager, Hindustan Construction Company Limited, Village Kalsui, P.O. Janghi via Mehla, District Chamba, H.P. not to reengage Shri Raj Kumar S/O Shri Kehar Singh workman after 01-09-2006 when the company re-started the work after strike/stoppage of work, whereas fresh workers/his juniors have been engaged by the company without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is legal and justified? If not, what relief of service benefits, back wages and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?”

Sd/-
Labour Commissioner,